



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 148]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली 13 जून, 2014

विषय : चीन.जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित भारी तथा मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियत फ्रंट एक्सल बीम एवं स्टीयरिंग नकल के आयातों पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

फा.सं. 15/11/2014-डीजीएडी.—1. यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 5 मार्च, 2010 को अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के तहत चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित भारी तथा मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियत फ्रंट एक्सल बीम एवं स्टीयरिंग नकल (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश की और उक्त अंतिम जांच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग ने दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 50/2010-सीमाशुल्क के तहत संबद्ध देश के मूल की या वहां से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

2. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पूर्व में समाप्त न किया जाए तो वह इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और उपर्युक्त उपबंध के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से उक्त उपाय की समाप्ति की तारीख से उचित समयावधि के भीतर किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर इस आशय की समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

3. और यतः उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार मै. भारत फोर्ज लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है । प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बारे में निर्णायक समीक्षा कार्रवाई की शुरुआत पाटन की समाप्ति हेतु ऐसे शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच करने और इस बात की जांच करने के लिए उचित होगी कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें परिवर्तन किए जाने या दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

घरेलू उद्योग

4. यह आवेदन संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से मै. भारत फोर्ज लि. द्वारा दायर किया गया है । रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

जांच की शुरुआत

5. समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत प्राधिकारी लागू शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत और इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा शुरू करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच में शामिल विचाराधीन उत्पाद "भारी एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियत फ्रंट एक्सल बीम तथा स्टीयरिंग नकल" है चाहे वह फोर्ज किया गया है अथवा मशीनीकृत हो। मूल जांच में दिनांक 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 14/19/2008-डीजीएडी के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र विस्तार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :—

"9.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जांच का दायरा और क्षेत्र विस्तार केवल चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित "भारी एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए नियत फ्रंट एक्सल बीम तथा स्टीयरिंग नकल" है और एक्सल का समग्र संयोजन इस जांच के क्षेत्र का भाग नहीं है।"

7. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है। इस अवधि के दौरान उत्पादों में कोई खास विकास नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने साक्ष्य प्रदान कर यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ कोड 73269099, 73261910, 73261990, 87085000 और 87089900 से किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समनुरूप है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में या तो तकनीकी विनिर्देशनों या फिर गुणवत्ता, कार्य एवं अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जांच अवधि

10. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 (9 माह) की थी। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने में कार्यकारी को समर्थ बनाने के लिए प्राधिकारी एतद्वारा जांच अवधि अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 (12 माह) के रूप में निर्धारित करते हैं। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2010-मार्च, 2011, अप्रैल, 2011-मार्च, 2012, अप्रैल, 2012-मार्च, 2013 की अवधि और प्रस्तावित जांच अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 14/19/2008-डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।

12. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के जरिए उसकी सरकार, संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित को लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
कमरा सं. 132, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना की तारीख से 40 (चालीस) दिन से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञान निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में 'उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर

सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समयावधि को बढ़ाने के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में दायर किया जाना चाहिए। प्रदान की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

16. किसी अंकन के बिना किया गया कोई अनुरोध अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकार को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

17. ऐसी सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए सूचना प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीकरण व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है, तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे। तथापि, पक्षकार यह नोट करें कि ऐसी सूचना पाटनरोधी नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

Subject: Initiation of Sunset Review of definitive anti-dumping duty imposed on imports of Front Axle Beam and Steering Knuckle meant for heavy and medium commercial vehicles originating in or exported from the China PR.

F. No 15/11/2014-DGAD.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had recommended to the Central Government imposition of the anti dumping duty on the imports of Front Axle Beam and Steering Knuckle meant for heavy and medium commercial vehicles (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) vide its Final Findings Notification dated 5th March, 2010. And, on the basis of the said Final Findings, the Department of Revenue, vide Notification No. 50/2010-Customs dated 12th April, 2010, had levied the definitive anti dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. and, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on

behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And, Whereas, in terms of the above provisions, M/s. Bharat Forge Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) representing the Domestic Industry have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for such a review, and the Authority on the basis of prime facie evidence considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

DOMESTIC INDUSTRY

4. The application has been filed by M/s. Bharat Forge Ltd. on behalf of the domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and, therefore, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

INITIATION

5. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

PRODUCTS UNDER CONSIDERATION

6. The products under consideration involved in the original investigation are 'Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles' whether forged or machined. In the original investigation, vide notification No. 14/19/2008-DGAD dated 5th March, 2010, the Designated Authority had defined the scope of products under consideration as under:

"9.1 It is clarified that ambit and scope of the present investigation is restricted to imports of 'Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles' originating in or exported from China PR only and the entire axle assembly is not a part of the scope of the investigation."

7. Present investigation being a review investigation, products under consideration remain the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the products over the period. The petitioner by supplying evidence claimed that the subject goods are imported with tariff codes 73269099, 73261910, 73261990, 87085000 and 87089900. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

COUNTRIES INVOLVED

9. The countries involved in the present investigation are China PR.

PERIOD OF INVESTIGATION

10. The Period of investigation (POI) proposed by the applicant was from April 2013 to December 2013 (9 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of audited accounts for the financial year 2013-14, the Authority hereby determines the POI as April 2013 to March 2014 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013 and the POI.

PROCEDURE

11. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 5th March, 2010.

12. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

SUBMISSION OF INFORMATION

13. The known exporters in the subject country and their Government through its Embassy importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India,

Room No. 132, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

TIME LIMIT

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information. *Parties, may however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-dumping Rule 7(1) and 7(2).*

INSPECTION OF PUBLIC FILE

21. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority